ब्लैक एंड ग्रेः आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

05 जनवरी, 2021

आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई दिखावे के लिए सही है, लेकिन इससे उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

ग्लोबल वॉचडॉग कहे जाने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की अगली बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के ऑपरेशन कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी, जो 2008 के मुंबई हमलों से जुड़ा हुआ था, की गिरफ्तारी ने भारत में पाकिस्तान के लिए संदेह को और गहरा कर दिया है। जब कभी भी पाकिस्तान को अपनी "ग्रे लिस्ट" स्थिति पर निर्णय का सामना करना पड़ा है, उसने ऐसी ही कार्रवाइयों को अंजाम दिया है ताकि वह FATF से खुद के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित कर सके।

जकी-उर-रहमान लखवी की गिरफ्तारी, आतंकी-वित्तपोषण मामलों में हाफिज सईद और अन्य लश्कर के नेताओं को दोषी ठहराया जाना, पाकिस्तान विधानसभा में आतंकवाद-रोधी और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को पारित करना, उन्हें FATF के अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप आने के लिए आतंकवादियों की नई सूचियों का प्रकाशन, हमेशा FATF की समीक्षाओं से पहले किया गया है। फरवरी में FATF पूर्ण सत्र के लिए पाकिस्तान की स्थिति पर अंतिम निर्णय के लिए FATF के एशिया प्रशांत संयुक्त समूह की जनवरी में बैठक होना है।

पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में वापस लाया गया था और अक्टूबर 2019 तक 27-पॉइंट एक्शन प्लान की सूची को पूरा करने के लिए आदेश दिया गया था। पाकिस्तान सरकार एफएटीएफ की कार्रवाई को रोकने और ग्रे सूची से बाहर आने के लिए अमेरिकी लॉबिंग कंपनी पर बार-बार भरोसा करती है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन को मनाने के लिए पाकिस्तान ने टेक्सास स्थित लिंडन स्ट्रेटजीज की सेवाएं ली हैं। इसके जरिये पाकिस्तान अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जो गंभीरता से आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है। हालांकि वास्तविकता कुछ और है। पाकिस्तान अब यह उम्मीद कर रहा है कि कार्ययोजना में उसकी प्रगति और जेल में कई प्रमुख आतंकी डालने के बाद वैश्विक स्तर पर उसकी छवि बेहतर हो जाएगी।

भारत का डर यह है कि अगर पाकिस्तान को छूट मिलती है, तो वह सभी कार्यों को फिर से पलट देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के डर से इन सभी आतंकवादियों की गिरफ्तारी की लेकिन बाद में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने बाद इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। पिछले महीने ही पाकिस्तान की अदालत ने अलकायदा नेता अहमद उमर शेख सईद की सजा को पलट दिया।

विदित हो कि अहमद उमर शेख सईद वही आतंकवादी है जिसके लिए भारत को 1999 के IC-814 अपहरण के दौरान रिहाई के लिए मजबूर किया गया था, साथ ही यह 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के लिए दोषी पाया गया था। पाकिस्तान का इस तरह का रवैया यह दर्शाता है कि पाकिस्तानी जांच एजेंसियां कैसे खुद को प्रस्तुत करती है और न्यायिक प्रणाली आतंकवाद पर किस तरह का कार्यवाही करती है।

हाफिज सईद को केवल आतंकी वित्तपोषण के आरोपों में दोषी ठहराया गया है और इसके लिए उसे लगभग छह साल की सजा का सामना करना पड़ेगा, इसी तरह लखवी को आतंकी वित्तपोषण के आरोपों में दोषी ठहराया गया है, जबकि इसका कई घातक आतंकी हमलों का लम्बा रिकॉर्ड रहा है। मसूद अजहर जैसे अन्य लोग संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद किसी भी तरह के अभियोजन से बचते रहे हैं। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई में FATF ग्रे लिस्टिंग (2012-2015 और 2018-अब तक) काफी सहायक हथियार सिद्ध हो सकती है।

FATF के ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान

संदर्भ

- पिछली बार पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा ग्रे लिस्ट में पिछले साल अक्टूबर में शामिल किया गया था।
- इसकी घोषणा एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लीयर ने की थी।
- फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई इस बैठक में कहा गया था कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल रहा है।

ग्रे सूची में क्यों रखा गया

- विदित हो कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान सरकार को 27 कार्य सौंपे थे।
- उसमें से पाकिस्तान ने 27 कार्ययोजनाओं में से केवल 21 को ही पूरा किया है।
- अब इसे पूरा करने की समय-सीमा खत्म हो गई है।

क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)?

- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में इसके सदस्य न्यायालयों के मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- इसे जी-7 की पहल पर स्थापित किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है।
- एफएटीएफ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक के मानकों को निर्धारित करना है।
- इसमें कुल 37 सदस्य देश हैं। इनमें 37 सदस्य देशों के साथ 2 क्षेत्रीय संस्थाएँ यूरोपियन कमीशन और गल्फ ऑफ को-ऑपरेशन कौंसिल भी शामिल हैं।
- भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया और सऊदी अरब इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हैं।
- एफएटीएफ अपने सदस्यों की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों और काउंटर-उपायों की समीक्षा और आवश्यक उपायों को लागू करने की प्रगति की निगरानी करता है।
- साथ ही विश्व स्तर पर किए जा रहे उपयुक्त उपायों को अपनाने और लागू करने को बढ़ावा देता है।

FATF की ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या हैं?

- FATF द्वारा 2 प्रकार की सूचियाँ जारी की जाती हैं-
- **ग्रे लिस्ट:** इस सूची का मतलब यह है कि जिस देश पर संदेह होता है कि वह ऐसी कार्यवाही नहीं कर रहा है जिससे कि आतंकवादी संगठन को फंडिंग न हो तो उसे 'ग्रे लिस्ट' में रखा जाता है।
- **ब्लैक लिस्ट:** यदि यह साबित हो जाए कि किसी देश से आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है और जो कार्यवाही उसे करनी चाहिये वह नहीं कर रहा है तो उसका नाम 'ब्लैक लिस्ट' में डाल दिया जाता है।

पृष्ठभूमि

- एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 में 'ग्रे' सूची में डाला था और इस्लामाबाद को धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की 27 बिंदुओं की कार्य योजना को वर्ष 2019 के अंत तक लागू करने को कहा था।
- कोरोना महामारी की वजह से इस अवधि में वृद्धि कर दी गई थी।
- गौरतलब है कि आतंकवाद को आर्थिक मदद देने के चलते पाकिस्तान वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक एफएटीएफ के 'ग्रे लिस्ट' में शामिल रह चुका है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना जी-7 की पहल पर किया गया था।
2. भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना और पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है।
3. इसके द्वारा तीन प्रकार की सूचियाँ जारी की जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 **(b)** केवल 1

(c) 2 और 3 **(d)** उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of 'Financial Action Task Force':-

1. It was founded on the initiative of G-7.
2. India became a member of FATF in the year 2010 and Pakistan is not a member of it.
3. Three types of lists are issued by it.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2 **(b)** Only 1

(c) 2 and 3 **(d)** All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे सूची और काली सूची क्या है? किसी भी देश पर इस सूची में आने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में FATF के महत्व पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. What is the gray list and black list of the Financial Action Task Force (FATF)? What effect does any country have after coming into this list? Discuss the importance of FATF in the context of India-Pakistan relations. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।